

संक्षिप्त समाचार

धान खरीदी की परेशानी से
बचने किसान 31 अक्टूबर तक
एग्रीस्टैक में पंजीयन कराएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। खरीद विपणन वर्ष 2026-27 में धान बेचने के लिए किसानों को अब राज्य सरकार पर एक क्लिक किसान पोर्टल पर अलग से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। धान खरीदी के लिए केवल केंद्र सरकार के एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। खाद्य विभाग ने इस संघर्ष में सभी कलेक्टरों, खाद्य संचालक और अपेक्षक बैंक के प्रबंध संचालक को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब सोसाइटीयों में भी एग्री स्टैक पंजीयन की सुविधा मिलेगी। एग्री स्टैक में पंजीयन कराने के लिए सोसाइटी के ऑफिसरों का लॉग इन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, ताकि किसान को पंजीयन के लिए भटकना न पड़े। साथ ही एक ही स्थान पर काम हो जाए। विभाग के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2026-27 में धान बेचने के लिए किसानों का रकबा सिर्फ एग्री स्टैक पोर्टल पर दर्ज डिजिटल क्रॉप सर्वे में दिखने वाले रकबे को ही मान्य किया जाएगा। जिन किसानों ने पिछले सीजन में धान नहीं बेचा और जिनके पास एग्री स्टैक फॉर्म आईडी की जानकारी को नहों है, उन्हें पहले पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। इसके बाद समिति या उपार्जन केंद्र में जाकर जमीन के खसरे का विवरण, बैंक डिटेल और नॉमिनी की जानकारी ऑनलाइन सोसाइटी मॉड्यूल में दर्ज करानी होगी। यह काम समिति द्वारा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में करीब 28 लाख से अधिक किसान पहले से एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीकृत हैं। अब भी लाखों की संख्या में किसान सूटे हुए हैं, इनके पास पंजीयन कराने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय है।

बलेनो कार में बना रखा था
सीक्रेट चेंबर, 53 किलो गांजा
जब्त; पुलिस को देख तस्कर फ़रार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सिंधोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एनएच-53 स्थित रेहटीखोल के पास एक लावारिस बलेनो कार से 52.990 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। तस्करों ने गांजा छिपाने के लिए कार की पिछली सीट और छत (रूफ) में विशेष सोक्रेट चेंबर तैयार किया था। पुलिस ने गांजा, कार और दो मोबाइल फोन समेत 29.51 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। पुलिस के मुताबिक, एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स के निर्देश पर ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मुखबिंद से सूचना मिली कि ओडिशा नंबर (ओडी 02 बीएफ 1372) की एक बलेनो कार में भारी मात्रा में गांजा लेकर तस्करी छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही सिंधोड़ा थाना पुलिस ने रेहटीखोल के पास नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को चेकिंग प्वाइंट से करीब 100 मीटर पहले सदिग्ध बलेनो कार लावारिस हालत में खड़ी मिली। आशंका है कि पुलिस की मौजूदगी देखकर तस्कर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। जब पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कार की तलाशी ली तो पिछली सीट और रूफ में बने गुप्त चेंबर से 52.990 किलो गांजा बरामद हुआ। जब गांज की अनुमानित कीमत 26.48 लाख रुपये, कार की कीमत 3 लाख रुपये और दो मोबाइल फोन की कीमत 2,500 रुपये आंकी गई है। इस तरह कुल 29.51 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। सिंधोड़ा थाना पुलिस ने फरार चालक के खिलाफ एनडीपीए एकट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

तेज रफ्तार बाइक ने शिक्षक को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कठघोरा थाना क्षेत्र में पत्नी को स्कूल छोड़कर लौट रहे एक शिक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बाइक ने शिक्षक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल शिक्षक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे में बाइक सवार युवक भी घायल हुआ है, जबकि बाइक पर पीछे बैठा दूसरा युवक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक, मृतक शिक्षक अजय थवाईट और उनकी पत्नी दोनों शिक्षक हैं। बुधवार सुबह अजय थवाईट रोज की तरह अपनी पत्नी को एक्टिवा से स्कूल छोड़ने पहुंचे थे। पत्नी को स्कूल गेट पर छोड़ने के बाद शिक्षक पैदल सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शिक्षक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे की सूचना मिलते ही कठघोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल शिक्षक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। हालांकि, गंभीर चोटों के कारण डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस सड़क हादसे में बाइक चला रहा युवक भी घायल हुआ है। उसे कठघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं बाइक पर पीछे बैठा दूसरा युवक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस प्रार युवक की तलाश में जुटी है।

रायपुर पश्चिम के 36 शासकीय विद्यालयों में लगेंगे आधुनिक वॉटर कूलर, हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा स्वच्छ पेयजल

रायपुर। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्क्व एवं शीटल पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यालय एवं पंचू कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत की पहल पर 36 सरकारी विद्यालयों में लगभग 25 लाख रुपये की लागत से आधुनिक वॉटर कूलर स्थापित किए गए हैं। इस पहल से हजारों छात्र-छात्राओं को वर्षभर स्क्व पेयजल की सुविधा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य केवल विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षण वातावरण को भी सुनिश्चित करना है। गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या के कारण बच्चों को होने वाली परेशानियों को रद्दते हुए पद निर्णय लिया गया। विद्यालय राजेश मूणत ने कहा कि विद्यालयों में किया गया प्रत्येक विकास कार्य भविष्य की पीढ़ी में किया गया निवेश है। उनका कहना है कि यदि बच्चों को बेहतर सुविधाएं और समानजक वातावरण मिलेगा तो वे समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रायपुर पश्चिम के सरकारी विद्यालयों में वॉटर कूलर के अलावा थार्थना, डा. अतिरिक्त कक्ष, परिसर विकास, वृक्षारोपण, स्वच्छता और अन्य आधारभूत सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।

पारस पोर्टल से हर माह होगी योजनाओं की राज्यस्तरीय समीक्षा संपन्न

■ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का करें समयबद्ध क्रियान्वयन , प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले शासन की योजनाओं का लाभ

जनहित की योजनाओं में
लापरवाही नहीं होगी
बर्दाश्त, मुख्यमंत्री साय ने
दिए स्पष्ट निर्देश

रायपुर/ संवाददाता

शासन की योजनाओं का प्रभावी, अपारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कर आमजन को अधिकतम लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। डबल इंजन सरकार का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित

करना है। इसी दृष्टि से शासन की प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की नियमित निगरानी के लिए विकसित पारस पोर्टल पर शासन का एक प्रभावी माध्यम बनना मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साधु ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पारस पोर्टल की पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साधु ने सीएम हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, एडीटर, विकसित भारत जी-रामजी, ड्रीमस्टार, वित्तपोषित मोबाइल टॉवर परियोजना तथा स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े प्रमुख कार्यक्रमों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम सुनिश्चित करे। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साधु ने राज्यस्तरीय समीक्षा के संर्बन्धित लॉन्चिंग मामलों पर विशेष नाराजगी व्यक्त



को। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद भी कई मामलों में समय पर सीमांकन नहीं हो रहा है। यह स्थिति आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी में डालती है तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमांकन संबंधी प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा

कि यह जमीनी स्तर पर लापरवाही तथा जिला स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव का परिणाम है। सभी कलेक्टर नियमित समीक्षा कर ऐसे मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करें। मुख्यांत्री श्री विष्णुदेव साय ने एग्रीस्टेक में प्रत्येक पात्र किसान का स्तर-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह केवल धान खरीदो की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है,

बल्कि किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध करने की आधारभूत व्यवस्था है। उन्होंने सभी कनेक्टरों को निर्देश दिए कि जिलेवार विशेष अभियान संचालित कर प्रत्येक पात्र किसान का समय पर पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष व्यवस्था के प्रारंभिक चरण में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ सामने आई थीं, लेकिन इस वर्ष किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही के कारण कोई पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित होता है तो संबंधित अधिकारी की जाचबंदी हो कर तब तक हुए कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साहू ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1076 का उद्देश्य नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से बचना है। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

सीएम हेल्पलाइन का असर: किसान अस्मलाल साहू की समस्या का तुरंत समाधान किया गया

**बेनूर समिति को
मिले शेष डीएपी
वितरण के निर्देश**

रायपुर/ संवाददाता

प्रदेश में सुशासन, जवाबदेही और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में मुख्यमंत्री हेलपलाइन प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री हेलपलाइन के जरिए आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान निश्चित किया जा रहा है, जिससे सुशासन के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हो रहा है। सुशासन की दिशा में सीएम हेलपलाइन शिकायतों के लिए एक भरोसेमंद माध्यम साबित हो रही है। नारायणपुर जिले के बेनूर सेवा

पेशान किसान अस्मलाल साहू ने अपनी समस्या को लेकर 16 जुलाई 2026 को सीएम हेलपलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। अस्मलाल साहू का कहना था कि एक हेक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त डीएपी खाद की आवश्यकता थी, लेकिन निर्धारित मात्रा का कृषक पुरा न होने के कारण खेती-किसानी प्रभावित हो रही थी। शिकायत मिलते ही कृषि और सहकारिता विभाग हरकत में आया। मार्कफेड द्वारा पहली ही बेनूर समिति की पर्याप्त मात्रा में



326.16 टन यूरिया और 245 टन डीएपी उपलब्ध कराया जा चुका था। समस्या की वस्तुस्थिति जानने के लिए अधिकारियों ने शिकायतकर्ता से मोबाइल नंबर पर सीधा संपर्क साधा। प्रकरण के त्वरित निपटारे के लिए विभाग ने किसान अम्सलाल साहू और बेनूर सोसायटी के प्रभारी उमेश नायक के बीच कॉन्फ्रेंस काल के

जिराए संवाद कराया। चर्चा के दौरान सोसायटी प्रभारी ने स्पष्ट किया कि किसान को पहले ही आंशिक मात्रा में खाद दी जा चुकी है। विभागीय निर्देशों के बाद समिति प्रभारी ने शेष आवश्यक डीएपी खाद नियमानुसार तत्काल उपलब्ध कराने की सहमति दी। समिति तत्पश्चात और समस्या के समग्रबद्ध समाधान पर किसान अस्मलाल साहू ने पूर्ण संतोष व्यक्त किया। आउटबाउंड सत्यापन कार्य में शिकायतकर्ता की सहमति मिलने के बाद सीएम हेलपलाइन में दर्ज प्रकरण को सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया। इस पहल ने एक बार फिर साबित किया है कि सरकार किसानों की हर समस्या के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

एक सप्ताह में मिला जाति प्रमाण पत्र

सेवा सेतु बना आमजन का
भरोसेमंद डिजिटल साथ.....

रायपुर/ संवाददाता

सरकारी सेवाओं को आम नागरिक तक सरल, त्वरित और आकर्षक तरीके से पहुंचाने की दिशा में सेवा सेतु प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। राजनंदगांव विकासखंड के ग्राम मोहड़ निवासी यादव राम चंद्राकर इसके उदाहरण हैं। उन्होंने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और मरुज एक सप्ताह के भीतर उसका प्रमाण पत्र सही हो गया। इससे न केवल उनका समय बचा, बल्कि कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने और अनावश्यक खर्च से भी बचने मिली। यादव राम चंद्राकर



बताते हैं कि पहले छोटे-छोटे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आवेदन की स्थिति जानने में भी काफी समय और मेहनत लगती थी। लेकिन सेवा सेवु ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन, अपरदर्शनी और नागरिक-अनुकूल बना दिया है। अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित

समय-सीमा में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने इस जनहितकारी पहल के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह व्यवस्था ग्रामीण नागरिकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो रही है। उल्लेखनीय है कि पहली प्रदर्शनी में 1-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल 86 शासकीय सेवाएँ उपलब्ध थीं। बलूची ज़रूरतों को देखते हुए इसका उन्नत संस्करण सेवा 114 तक विस्तारित किया गया, जिसमें अब 44 से अधिक शासकीय सेवाएँ एक ही ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध हैं। इससे शासन की सेवाएँ अधिक सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध हुई हैं।

लिव-इन में रह रही
युवती की हत्या,
युवक गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामल सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही एक आदिवासी युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस इस हत्या का मामल मानकर जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई जानकारी के मुताबिक, युवती अपने साथी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आशका है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद युवती की हत्या कर दी गई। हालांकि, घटना के पीछे का वास्तविक वजह पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि

किसानों की आय में वृद्धि और हरित अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल

सीबीजी इकोसिस्टम के विकास के लिए भारत सरकार ने स्वीकृत किए 50 करोड़ रुपये

स्वच्छ ऊर्जा, किसानों की आय में वृद्धि और हरित अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। राज्य में कर्मस्वच्छ विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रभावितों और प्रभावी प्रयासों के अन्तर्गत जा रहे नवाचारों और भारत सरकार के समर्थन सहित हुए भारत सरकार के मेट्रोपॉलिटन एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने

पूँजीगत निवेश विशेष सहायता योजना 2026-27 के अंगत छत्तीसगढ़ को 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत यह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेवराय साहू ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अगुवाई पहचान बना रहा है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग तथा छत्तीसगढ़ बायोमैसूर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इस सफलता के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की ईंधन प्रमुख बायोगैस नीति राज्य के कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी। इससे कृषि अवशेषों को



वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित होगा, किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिलेगा तथा पराली और अन्य जैव अवशेषों का बेहतर प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए हरित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को जैव ईंधन एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी

राज्य बनाना है। सीबीजी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में निवेश, रोजगार, किसानों की आय, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण को नई गति मिलेगी तथा विकासित छत्तीसगढ़ के संकल्प को राज्य और अधिक मजबूती प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने कम्प्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 को 8 जुन 2026 को अधिसूचित किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कुपि अपशिष्ट,

पेडी स्ट्रू तथा अन्य बायोमास का वैज्ञानिक रूपान्तरण कर औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्वच्छ गैसीय ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। इससे किसानों को बायोमास की आपूर्ति से अतिरिक्त आय प्राप्त होगा, वहीं संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद और जैविक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शना में राज्य सरकार ने सीबीजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वित कार्यप्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर दिया है। इसी क्रम में 3 अगस्त 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग श्री सुबोध कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में सीबीजी परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए बायोमास संग्रहण व्यवस्था, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, जैव उर्वरक के उपयोग, विभागीय समन्वय तथा निवेश प्रोत्साहन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

